भारतीय जनता पार्टी

श्री लालकृष्ण आडवाणी का वक्तव्य
नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा

भुवनेश्वर : 24 सितम्बर, 2008

आज मैंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के साथ प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। महानदी और उसकी सहायक नदियों में आई बाढ़ तथा तत्पश्चात् भारी वर्षा के फलस्वरूप भयंकर विनाश हुआ है। काफ़ी बड़ी संख्या में जनहानि हुई है। उड़ीसा के 30 में से 18 जिलों के लगभग 48 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। मुझे बताया गया है कि सवा लाख से ज्यादा लोग अभी भी असहाय हैं।

बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित जिलों में पश्चिमी जिले बोलांगीर, कालाहांडी और बोद्ध तथा तटवर्ती जिलों केन्द्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, पुरी और भद्रक प्रमुख हैं। बाढ़ की विभीषिका वास्तव में चिन्ता का विषय है।

मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने स्थिति का अनुकरणीय सतर्कता और तत्परता से सामना किया। यह स्पष्ट है कि प्रदेश को तुरन्त राहत कार्य चलाने और तत्पश्चात पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण हेतु कदम उठाने के लिए केन्द्र से काफी बड़ी मात्रा में सहायता की आवश्यकता होगी।

केन्द्र सरकार ने प्रारंभिक सहायता के तौर पर 500 करोड़ रुपये घोषित किए हैं। यद्यपि बाढ़ द्वारा किए गए विनाश को देखते हुए यह एकदम अपर्याप्त हैं।

उड़ीसा सरकार ने केन्द्र को प्रारंभ में 2450 करोड़ रुपये की वितीय सहायता देने का ज्ञापन सौंपा है। मैं यू.पी.ए. सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राजनीतिक कारणों से उड़ीसा के साथ भेदभाव न करे।

केन्द्र को अवश्य ही राज्य सरकारों के सहयोग से उड़ीसा, बिहार, असम, और अन्य प्रदेशों में बाढ़ नियंत्रण के दीर्घकालिक उपायों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

मैं, नौसेना और अर्धसैनिक बलों को उनके द्वारा किए गए अथक बचाव एवं राहत कार्यों के लिए बधाई देना चाहता हूं। साथ ही अन्य स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए गए प्रयास भी प्रशंसा के पात्र हैं।

****

चूंकि मैं उड़ीसा में हूं इसलिए पिछले दिनों प्रदेश में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अत्यधिक पूजनीय हिन्दू नेता स्वामी लक्ष्मणानन्दा और तीन अन्यों की हत्या भड़काने वाली और अत्यंत निन्दनीय है। इस अपराध के दोषियों को अवश्य ही पकड़कर दंडित किया जाना चाहिए। साथ ही, इस अपराध के पीछे के उद्देश्य को उजागर करने की आवश्यकता है।

साथ ही, इस घटना की हिंसक प्रतिक्रिया जिसमें चर्चों पर हमले और अनेक निर्दोष ईसाई मारे गए, भी निन्दनीय है। दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे घटनाओं की पुनरावृति उड़ीसा या देश के किसी अन्य भाग में भी नहीं होनी चाहिए।

समय आ गया है जब हम किसी भी मज़हब द्वारा जबरदस्ती, प्रलोभन अथवा दूसरे धर्म की मिथ्या निन्दा करके मतांतरण करने के विरूद्ध एक सुदृढ़ राष्ट्रीय सहमति बनाने के उद्देश्य से मज़हबी मतांतरण के मुद्दे पर खुलकर लोकतांत्रिक ढंग से बहस करें। हालांकि मतांतरण के विरूद्ध अभियान किसी समुदाय के विरूद्ध अभियान नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए। धर्म के नाम पर हिंसा या उपद्रवों को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

****